

प्रेषक

एस0 के0 माहेश्वरी,  
सचिव  
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2007

विषय: 04 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु  
धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन-4/11071/जीर्ण-शीर्ण भवन निर्माण/ 2006-07 दिनांक 12-6-2006 एवं पत्र संख्या नियोजन-4/15343/जीर्ण-शीर्ण/2006-07 दिनांक 4-7-2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्न 04 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ-3 पर उल्लिखित कार्यदायी निर्माण संस्थाओं द्वारा गठित आगणनों के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा स्तम्भ-4 पर अनुमोदित कुल लागत रू0 341.00 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ -5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 134.00 लाख (रुपये एक करोड़ चौतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रशुभगत योजना में शासनादेश संख्या: 233/ XXIV-3/2006 दिनांक 27-4-2006 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 3090.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	निर्माण संस्था का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
रूढ़प्रयाग	1. रा0इ0का0 चमकोट	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर, पौड़ी	84.05	33.05

	2. रा0इ0का0 सिदसौड़	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर, पौड़ी	85.70	33.70
	3. रा0उ0गा0वि0 पाण्डवथली	- तदैव-	89.00	35.00
टिहरी	4. रा0इ0का0 घारी धुन्सीर,	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर, पौड़ी	82.25	32.25
योग-			341.00	134.00

- (1)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
- (2)- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- (3)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (4)- एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।
- (5)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
- (6)- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- (7)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

- (8)- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- (9)- जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
- (10)- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV- 219(2006)दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- (11)- निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखी जायेगी।

3- गुणवत्ता/ प्रगति की अनुश्रवण हेतु(Third Party Checking)की व्यवस्था प्राथमिकता पर बनायी जाय। इस पर होने वाला व्यय सेट्टेज चार्ज से ही किया जायेगा। अनुश्रवण की एक प्रति प्रशासकीय विभाग के साथ-साथ वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा- 202-माध्यमिक शिक्षा- आयोजनागत - 00- 11- राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण - 24- वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।



6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 638 / वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2007 दिनांक 20 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस० के० माहेश्वरी )  
सचिव

संख्या: 270 ( 1)/XXIV-3/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल- पौड़ी।
- 6- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल- पौड़ी।
- 7- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग, टिहरी।
- 8- कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग, टिहरी।
- 9- जिला शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग, टिहरी।
- 10- वित्त अनुभाग-3 /नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
- 12- संबंधित निर्माण एजेन्सी।
- 13- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
- 14- एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)  
उप सचिव